रंजीत टाइम्स

वर्ष : 1, अंक: 94 इंदौर, शनिवार 8 मार्च 2025

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

DIGITAL EDITION

आगामी त्यौहारो को मद्देनजर रखते हुए, पुलिस कमिश्नर इंदौर ने नगर सुरक्षा समिति सदस्यों के साथ किया बैठक का आयोजन

नगर सुरक्षा समिति के कार्यो की सराहना कर, पुलिस के साथ इसी प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर, और बेहतर काम करने का किया आव्हान

रंजीत टाइम्स » इंदौर

आगामी त्यौहारों होली/रंगपंचमी व रमजान आदि के दौरान शहर में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तथा शहर में शांति व्यवस्था एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाए इसी को मद्देनजर रखते हुए, इस दौरान आमजन की भी हर प्रकार से सहभागिता हो, इसी उद्देश्य से, पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा नगरीय इंदौर में कार्यरत् नगर सुरक्षा समिति सदस्यो के साथ एक बैठक का आयोजन आज दिनांक 07.03.25 को पलासिया स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सभागार में किया गया। उक्त बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) नगरीय इन्दौर अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) नगरीय इन्दौर मनोज कुमार श्रीवास्तव की उपस्थिति में नगर सुरक्षा समिति के जिला संयोजक रमेश शर्मा व अन्य पदाधिकारीगण तरणजीत सिंह छाबड़ा,जुगल किशोर गुर्जर सहित सभी एसीपी संयोजक, थाना संयोजक व बड़ी संख्या में नगर सुरक्षा समिति के महिला व पुरूष सदस्यगण सम्मिलित हुए।

पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह द्वारा सभी सदस्यगणों को संबोधित करते हुए कहा कि, आप सभी हमारे इंदौर पुलिस परिवार का अभिन्न अंग है, आप सभी समाज के वो सजग प्रहरी हो, जो पुलिस की आंख व कान बनकर, समाज की बुराईयों व अपराधिक गतिविधियों पर विराम लगा सकते हो। आप सभी किसी भी उत्सव/त्यौहार व कानून व्यवस्था की स्थिति में पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पूरी सजगता, मुस्तैदी व संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी करते है। पूर्व मे भी आप सभी ने ये दायित्व बखूबी निभाया है, और आगामी त्यौहारो के दौरान भी पूरी लगन व मेहनत से इंदौर पुलिस के सहभागी बनेगें, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इस अवसर पर एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह एवं एडिशनल कमिश्नर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने भी नगर सुरक्षा समिति सदस्यों के कार्यो की सराहना कर, उन्हें आगे भी इसी प्रकार पुलिस के अनुषंगी संगठन के रूप में कार्य करने के लिये प्रेरित किया। नगर सुरक्षा समिति जिला संयोजक रमेश शर्मा जी की अगुवाई में सभी सदस्यों ने एकमत होकर ये आश्वासन दिया कि, सभी नागरिकगण पूरे हर्षोल्लास व शांति के साथ उक्त त्यौहारों को मनाएं, इसके लिये वे सभी पूरी लगन, मेहनत और सजग होकर, पुलिस को हरसंभव सहयोग करेगें।

विजयवर्गीय बोले

होली खेलना इस्लाम के विरुद्ध नहीं हमारे साथ होली खेलें मुस्लिम भाई

रंजीत टाइम्स » इंदौर

एक नम्बरी विधायक और काबिना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज विजय नगर स्थित मंगल सिटी मॉल पहुंचे और उन्होंने यहां छावा मूवी देखी... उनके साथ मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित उनके पुत्र और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय और कांग्रेस से भाजपा में कूदे अक्षय कांति बम सहित अन्य समर्थक मौजूद थे... फिल्म देखने के बाद विजयवर्गीय ने मीडिया से कहा कि - ''मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल रखना चाहिए... जुमे की नमाज हर शुक्रवार आती है, लेकिन होली साल में एक बार... वे भी हमारे साथ होली मनाएं और इस त्योहार का मजा लें... विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि होली खेलना इस्लाम के विरुद्ध नहीं है और हमारे यहां तो गंगा-जमुनी संस्कृति रही है... हम एक-दूसरे को गुलाल लगाते आ रहे हैं... अब पता नहीं कहां से कट्टरवाद आकर मुस्लिम भाइयों में भ्रम पैदा कर रहे हैं... कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि मुस्लिम भाई अपने पूर्वजों का पता लगाएं... आपके पूर्वजों ने तो वृंदावन में कृष्ण के साथ भी होली खेली है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए!

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना की लाभार्थी महिलाओं का इंतजार खत्म होने वाला है

सभी पात्र लाभार्थियों के खातें में जल्द ही 3000 रुपये की सम्मान निधि जमा की जाएगी

मेहबूब शेख

महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। राज्य की 2.40 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों के खाते में अगले 24 से 36 घंटों में आठवीं और नौवीं किस्त जमा हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाडकी बहिन योजना की लाभार्थी महिलाओं खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू होगी। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने इसकी पुष्टि की थी। तटकरे के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर पात्र लाडली बहनों को दोनों महीने- फरवरी और मार्च की किश्ते एक साथ दी जाएंगी। यानी लाडली बहनों को एक साथ कुल 3000 रुपये मिलेंगे।

महाराष्ट्र सरकार 1 जुलाई 2025 से लाडकी बहिन योजना के तहत गरीब महिलाओं के बैंक खातें में हर महीने 1500 रुपये जमा करती हैं। अब तक जनवरी तक की सात किस्तें लाभार्थी महिलाओं को मिल चुकी हैं। लेकिन तकनीकी समस्या के चलते लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) की फरवरी की आठवीं किस्त नहीं दी गई।

महिला दिवस का तोहफामंत्री

अदिति तटकरे ने ट्वीट कर कहा, "लाडली बहनों को महिला दिवस का तोहफा! महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को फरवरी और मार्च माह का लाभ दिया जाएगा। 7 मार्च तक सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में दो माह की सम्मान निधि 3000 रूपये जमा कर दी जायेगी!"

2100 रुपये के लिए करना होगा इंतजार?

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति के नेताओं ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये किया जाएगा। चूंकि राज्य में महायुति सरकार दोबारा सत्ता में आ चुकी है, इसलिए लाभार्थी महिलाएं 2100 रुपये मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहीं है। महाराष्ट्र के मौजूदा बजट सत्र में इस पर बड़ी घोषणा होने की संभावना है। लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे के सदन में दिए जवाब से लाडली बहनों को बड़ी निराशा हुई है। शिवसेना (उद्धव गुट) विधायक अनिल परब के सवाल पर अदिति तटकरे ने कहा, राज्य के मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री की ओर से 2100 रुपये किस्त कब से दी जाएगी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जब सरकार किसी योजना की घोषणा करती है तो वह पांच वर्षों के लिए होती है। बजट में इस संबंध में फैसला लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल 2100 रुपये की कोई घोषणा नहीं की गई है।

पुणे में बनेंगे 5 स्टार पब्लिक टॉयलेट

सरकार ने किया ऐलान

महाराष्ट्र में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (पीएमसी) का बजट पेश किया गया. इस बजट में लोगों के हित में कई ऐलान किए गए. इसमें म्युनिसिपल कमिश्नर राजेंद्र भोंसले का एक ऐलान बेहद दिलचस्प रहा. अभी तक आपने फाइव स्टार होटल का नाम सुना होगा, लेकिन उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान शहर में फाइव स्टार टॉयलेट बनवाने की घोषणा की।उन्होंने कहा कि इस फाइव स्टार टॉयलेट के बन जाने के बाद बाहर से आने वाले लोगों को काफी सुविधाएं मिल सकेंगी. फिलहाल, उन्हें फ्रेश होने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है. कई मौकों पर उन्हें होटल में कमरा तक बुक करना पड़ता है. अब इस समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगी।

नगरपालिका का बजट पेश करते हुए, राजेंद्र भोंसले ने कहा कि पुणे में बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं. इस दौरान उन्हें कपड़े बदलने, तरोताजा होने और खुद को कहीं जाने के लिए तैयार होने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस समस्या को काफी दिनों से देखा जा रहा है. इसे ध्यान में रखते हुए, पीएमसी ने बेहतर सुविधाओं वाले शौचालय को बनाने की योजना बनाई है. ये शौचालय खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे, जो पुणे में काम के सिलसिले में आते हैं।

क्या-क्या मिलेगा?

पुणे नगरपालिका कमिश्नर राजेंद्र भोंसले ने कहा, 'फाइव स्टार टॉयलेट में हम यात्रियों को फ्रेश होने के साथ-साथ क्लॉक रूम की भी सुविधा देंगे, ताकि वो अपने जरूरी सामान को उसमें रख सकें और निश्चिंत होकर फ्रेश हो सकें. हमारी कोशिश है कि लंबी यात्रा कर पुणे पहुंचने वाले लोगों को साफ और अच्छा रेस्टरूम मिले. इन शौचालयों में साफ-सफाई के साथ आवश्यक सुविधाएं भी मिलेंगी।

कहां-कहां होंगे ये शौचालय?

नगरपालिका कमिश्नर के मुताबिक, इन शौचालयों का निर्माण शहर के हर एक एंट्री पॉइंट्स, अलग-अलग दिशाओं में जाने वाले रास्तों के बीच, खासकर सोलापुर हाईवे, अहमदनगर हाईवे पर किया जाएगा इसके अलावा शहर अन्य प्रमुख जगहों पर भी इसे बनाया जाएगा हर जगह शौचालय के साथ ही पार्किंग की भी सुविधा दी जाएगी।

पहले से बने टॉयलेट्स की हालत खराब

सरकार भले ही शहर में फाइव स्टार टॉयलेट बनाने की बात कर रही हो, लेकिन पहले से बने ई-टॉयलेट्स की हालत बेहद खराब है. लोगों ने बताया कि इन ई-शौचालयों को बनाने पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए लेकिन उनमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं है. उनकी हालत बेहद खराब है।

मुंबई के बीकेसी में

एप्पल से सस्ती जगह पर होगा टेस्ला का शोरूम
कंपनी ने भारत में एंट्री की ऐसे की तैयारी

प्रवेश सिंह

मुंबई दुनियाभर में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए मशहूर एलन मस्क की कंपनी टेस्ला अब भारत में दस्तक देने को तैयार है। कंपनी ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में अपना पहला शोरूम खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके लिए टेस्ला हर महीने करीब 35.26 लाख रुपये का किराया चुकाएगी। दिलचस्प बात यह है कि एप्पल इंडिया का ऑफिस भी इसी प्रीमियम लोकेशन पर है। कंपनी ने भारतीय बाजार में एंट्री के लिए क्या तैयारी की है,

एलॉन मस्क की कंपनी भारत में प्रवेश करने के लिए तैयार है। कंपनी ने अपना पहला शो रूम देश की वित्तीय राजधानी मुंबई के ब्रांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। कंपनी ने इस शो रूम पांच साल के लिए लीज पर लिया है। जिसका किराया 881 रुपये प्रति वर्ग फुट है, जो कि सबसे महंगा लीज रेंटल किराया माना जा रहा है। कंपनी को हर महीने 35.26 लाख रुपये का किराया देना होगा और हर साल 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। टेस्ला इंडिया ने एग्रीमेंट के तहत 2.11 करोड़ रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जाम किए हैं। कंपनी का यह शो रूम 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, ग्राउंट फ्लोर, यूनिट जी वन बी में है। इस बिल्डिंग में सभी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हैं और यह हाई एंड ऑफिस बिल्डिंग है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की यह पहली बड़ी डील नहीं है। इससे पहले एपल इंडिया ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक ऐतिहासिक डील के साथ कर्मिशयल रियल एस्टेट लीजिंग में एक नया रिकॉर्ड बना चुका है। रियल एस्टेट ट्रेकर प्रोपस्टेक के अनुसार कंपनी ने मेकर मैक्सिट-5 बिल्डिंग में 738 रुपये प्रति वर्ग फुट की मासिक किराय की दर पर 6,526 वर्ग फुट का ऑफिस लिया। यह भी पांच साल के लिए लीज पर लिया गया है और यह सौदा दिसंबर 2024 में पंजीकृत हुआ। एप्पल ने इसके लिए हर महीने 48.19 लाख रुपये देने की सहमति दी है और इस एग्रीमेंट में 4.33 लाख रुपये जमा किए गए हैं, साथ ही इसका लॉक इन पीरियड 31 दिसंबर 2027 को समाप्त होगा।

भारत में लीज ऑफिस बाजार का होगा विस्तार

प्रॉपट्री विशेषज्ञ अजय दिवान बताते हैं कि एप्पल से पहले जून 2024 में एक और सौदा जो कि अग्नि कॉमेक्स एलएलपी ने आईएमसी इंडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को 700 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से 5,830 वर्ग फुट की जगह लीज पर दी थी। इस सौदे ने सबसे पहले बीकेसी में सबसे महंगे ऑफिस लीज की रिकॉर्ड बनाया था। टेस्ला और एप्पल की वजह से बीकेसी क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों का दिलचस्पी बढ़ेगी। कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस पहले से यहां हैं और आनेवाले समय यह जगह और भी महंगी होने की संभावना है।

अवैध सट्टे कसरावद शहर के पांच ठिकानों पर चल रहा है

कसरावद शहर में चल रहे अवैध सट्टे की रोकथाम को लेकर पुलिस ने सट्टा माफिया सौरभ व चंदर दास को पकड़कर की कार्रवाई

शिवकुमार राठौड़

कसरावद थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन ने अपने स्टाफ सहित सभी चौकी प्रभारियों को कार्रवाई के लिए कहा है।

कसरावद नगर सहित क्षेत्र में भी कई जगह सट्टा खेला और खिलाया जा रहा है। इस मामले में कसरावद थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन को गोपनीय सूचना मिली तो उन्होंने दबिश दिलवाई। शहर के नया बस स्टैंड के पास सौरभ पिता चंदर दास बैरागी 26 वर्ष ,चंदर दास बैरागी 63 वर्ष द्वारा कसरावद नया नगर में सट्टा लिखते हुए दो बाप बेटों को पुलिस ने सट्टा सामग्री एवं दो मोबाइल नगद राशि 1760 रुपए जप्त किया है। वहीं नगर में चल रहे इस अवैध कारोबार पर अंकुश के लिए पुलिस जानकारी जुटा रही है। इसी प्रकार शहर के अलग-अलग वार्डों में अवैध रूप से सट्टे का कारोबार बड़े तेजी से फल फूल रहा है। कसरावद नगर परिषद के सामने, कसरावद नगर के ब्राह्मण मोहल्ला काला डेरा मंदिर के सामने कसरावद डाक बंगले के गेट पर और महिला बाल विकास के गेट पर अवैध रूप से सट्टा का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। बता दे पकड़े गए आरोपी का पहले भी अवैध रूप से सट्टा लिखने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। लेकिन इसके बावजूद वह इस गैर कानूनी धंधे में लिफ्ट रहा आरोपी आज भी अवैध रूप से सट्टा लिखने का काम कर रहा है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल दो आरोपियों के विरूद्ध थाना कसरावद पर धारा 4 क अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

अपराधों से बचाव के लिए चलाया अभियान

दीपक तोमर खरगोन जिला

सनावद।पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण के साथ अपराधों से बचने के लिए भी जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश व थाना प्रभारी रामेश्वर ठाकुर के मार्गदर्शन में पुलिसकर्मियों ने गुरुवार को थाना क्षेत्र में साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिसकर्मियों ने नगर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों व स्कूलों में विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों को साइबर अपराधों की जानकारी दी गई और बचाव के लिए सतर्क किया। पुलिसकर्मियों ने बताया किसी भी प्रकार का फ्रॉड होने की आशंका पर तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इससे साइबर अपराधों के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सेल सक्रिय रूप से काम कर रही है। ऑनलाइन मित्रों द्वारा आपातकालीन स्थिति में मांगे गए पैसों या महंगे गिफ्ट के नाम पर कस्टम ड्यूटी की मांग से सावधान रहे। इस अभियान के तहत लोगों को कई जरूरी सावधानियों की जानकारी दी जा रही है। इससे वह ठगी का शिकार ना हो। पुलिस ने नगर में साइबर अपराध से बचाव की जानकारी देने वाले पैम्पलैट वितरित किए। इस दौरान एसआई चैनसिंह सोलंकी, केएस डावर, आरक्षक अजय सिंह सोलंकी उपस्थित थे।

रणजीत टाइम्स
इंदौर, शनिवार 8 मार्च 2025
03
DIGITAL EDITION

पीएम आवास आवंटन को लेकर सदन में बड़ा हंगामा

पूर्व सीएम बघेल ने सरकार को घेरा तो डिप्टी सीएम ने आंकड़ों के साथ दिया जवाब

अजय शर्मा

प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्माती रही है और सियासी घमासान मचता रहा है. पीएम आवास को लेकर सियासत ऐसी कि 2023 में बीजेपी ने मुद्दा बनाया और प्रदेश में सरकार बना ली. अब एक बार फिर कांग्रेस ने पीएम आवास को लेकर साय सरकार को सदन में घेरा है. पूर्व सीएम भूपेष बघेल ने सदन में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों में अंतर को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से जवाब मांगा, जिसपर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस विधायक हंगामा करते हुए सदन से वॉक आउट कर गए।

प्रश्नकाल में हुआ हंगामा

पीएम आवास को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, 'प्रश्नकाल में सदन में प्रधानमंत्री आवास का साधारण प्रश्न पूछा गया. 2016 रमन कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास का काम पूरा नहीं हुआ. कांग्रेस पर आरोप लगाया गया

कि कांग्रेस शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ. आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे. 6 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस कार्यकाल में बने. आंकड़ों के अनुसार, सरकार का झूठ पकड़ा गया. 2011 के सर्वे सूची के आधार पर आवास योजना बनी थी. सदन में उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास पर सबको गुमराह किया।

पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने दिया जवाब

भूपेश बघेल के सवाल का पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा, 'छत्तीसगढ़ में कुल 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने हैं. सरकार 18 लाख आवास बनाने का काम कर रही है. भूपेश कार्यकाल में 3 लाख प्रधानमंत्री आवास बने हैं. छत्तीसगढ़ में कुल 11 लाख 58 हजार 919 आवास बने है. साय सरकार में 2 लाख से अधिक आवास बनाए गए. केंद्र ने 17 राज्यों को आवास प्लस में आवास दिए हैं. भूपेश सरकार ने सभी आवास को अमान्य कर दिया था।

क्या है पीएम आवास योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान, 2015 में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी. इस योजना में 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए सभी राज्यों के लिए पीएम आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. इसके तहत छत्तीसगढ़ में कुल 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए गए. इस योजना के तहत हितग्राहियों को केंद्र सरकार 60 फीसदी राशि उपलब्ध कराती है. राज्य सरकार को 40 फीसदी राज्यांश के रूप में देना होता है।

पहले भी हुई है मुद्दे पर राजनीति

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में पीएम आवास में काम नहीं होने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने विभाग से इस्तीफा दे दिया था. इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को लगातार घेरा, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिला. वहीं, सत्ता में आते ही साय कैबिनेट की पहली बैठक में ही 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दी गई।

एंटी नक्सल फोर्स को किया जाएगा भंग,कर्नाटक नक्सल मुक्त हुआ- सीएम सिद्धरमैया

बेंगलुरू । कर्नाटक विधानसभा में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है. शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया है और इसलिए नक्सल विरोधी बल (ANF) को भंग कर दिया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने साइबर अपराध प्रभाग को मजबूत करने की भी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में कानून और व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों से निपटने के लिए कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई गई है. हमारी सरकार के कार्यकाल के समय 6 अंडरग्राउंड नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है

इसके साथ ही कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है इसलिए नक्सल विरोधी बल को भंग कर दिया जाएगा. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लाया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा 667 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु सेफ सिटी परियोजना को अमल में लाया जाएगा. इस परियोजना के तहत पूरे शहर में 7500 कैमरे लगाए गए हैं जबकि 10 ड्रोन और शरीर पर लगाने वाले 560 कैमरे भी उपलब्ध कराए गए हैं. महिलाओं में सुरक्षा को देखते हुए और अपराध की चपेट में आईं महिलाओं व बच्चों को तुरंत पुलिस सहायता सुनिश्चित करने के लिए शहर भर में कुल 60 महिला चौकियां स्थापित की गई हैं. इसके अलावा सात पुलिस थानों को भी निर्माण किया जाएगा।

नक्सलगढ़ में फर्जी सिम बेचने का खेल... ग्रामीण के दस्तावेज लेकर फर्जीवाड़ा

कांकेर। छत्तीसगढ़ के बस्तर को नक्सलवाद का गढ़ माना जाता है. इनमें से एक उत्तर बस्तर कांकेर भी है. यहां ग्रामीणों के दस्तावेज लेकर फर्जी तरीके से सिम बेचने का ताजा मामला सामने आया है. मामले में कांकेर पुलिस ने एक निजी टेलीकॉम कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार किया है. इस घटना को लेकर पूरे इलाके में चर्चा तेज है. कांकेर जिला एसपी का मामले में कहना है कि इसमें नक्सल एंगल को ध्यान में रखकर भी जांच की जा रही है।

ऐसे करता था धोखाधड़ी

पुलिस से मिली जनाकारी के अनुसार, आरोपी का नाम उत्कर्ष मिश्रा बताया जा रहा है. ये सिम रिप्लेस करने के बहाने दो बार केवाईसी कर ग्रामीणों के व्यक्तिगत दस्तावेज के आधार पर अतिरिक्त सिम जारी कर धोखाधड़ी करता था और उक्त सिम को बेच दिया करता था. आरोपी ने अब तक फर्जी तरीके से धोखाधड़ी कर 188 ग्रामीणों के नाम सिम बेचा था. कांकेर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि चुकी इलाका नक्सल प्रभावित है, इसलिए नक्सल एंगल को लेकर भी जांच की जा रही है।

नक्सल एंगल पर भी ध्यान

पुलिस ने फर्जी सीम के मामले में इलाके के एक निजी टेलीकॉम कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार किया है. इसके कुल 188 ग्रामीणों के नाम पर फर्जी सिम बेचने का मामला उजागर हुआ है. कांकेर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण इसमें नक्सल एंगल से भी जांच की जाएगी. साथ ही, और कोई इस तरह की आपराधिक गतिविधि तो नहीं हो रही, इसकी भी जांच की जाएगी।

जब तक तुम ये पढ़ोगी, मैं जा चुका होऊंगा', पत्नी पर आरोप लगाते हुए एनिमेटर ने क्या-क्या लिखा

प्रवेश सिंह/मेहबूब शेख मुंबई

मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक 41 वर्षीय एनिमेटर निशांत त्रिपाठी ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. ये कदम उठाने से पहले निशांत ने अपनी कंपनी की वेबसाइट पर एक सुसाइड नोट पोस्ट किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी अपूर्वा पारीक और उसकी मौसी को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

पालघर के रहने वाले निशांत सुसाइड से तीन दिन पहले विले पार्ले के एक होटल में आकर ठहरे थे. 28 फरवरी को उन्होंने फांसी लगा ली. सुसाइड नोट में निशांत ने अपनी पत्नी को लेकर लिखा- 'Hi babe, जब तक तुम ये पढ़ोगी, मैं जा चुका होऊंगा. मेरे आखिरी लम्हों में मैं तुमसे नफरत कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं. इस पल के लिए मैं सिर्फ प्यार को चुनता हूं. मैंने तुमसे तब भी प्यार किया था, अब भी करता हूं और जैसा वादा किया था, मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा।

सुसाइड नोट में निशांत ने अपनी मां के लिए लिखा कि 'मां जानती हैं कि मेरी बाकी परेशानियों के अलावा, तुम (अपूर्वा) और तुम्हारी मौसी प्रार्थना भी मेरी मौत की जिम्मेदार हो. इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अब मां के पास मत जाना. वह पहले ही पूरी तरह टूट चुकी हैं, उन्हें शांति से शोक मनाने दो.'सुसाइड नोट के अंत में निशांत ने अपनी पत्नी के लिए एक कविता भी लिखी, जिसमें अपने प्यार का इजहार किया।

होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव

बता दें कि निशांत ने सुसाइड करने से पहले कमरे के दरवाजे पर 'डू नॉट डिस्टर्ब' का साइन लगा दिया था. जब कई घंटों तक दरवाजा नहीं खुला, तो होटल स्टाफ ने मास्टर चाबी से दरवाजा खोला और अंदर उसका शव लटका मिला इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई

पत्नी और मौसी पर केस दर्ज

पुलिस जांच में निशांत का सुसाइड नोट उसकी कंपनी की वेबसाइट पर मिला. निशांत की मां, जो कानपुर में रहती हैं, उन्होंने अपनी बहू अपूर्वा और उसकी मौसी प्रार्थना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपूर्वा पर BNS धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

पुरुषों के अधिकारों और जेंडर न्यूट्रल कानूनों पर बहस तेज

इस मामले ने एक बार फिर पुरुषों के अधिकार और जेंडर न्यूट्रल कानूनों पर बहस छेड़ दी है. इससे पहले बेंगलुरु के टेक्निकल इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला भी चर्चा में था. अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे. अतुल का शव उसके फ्लैट में लटका मिला था, जहां उसने 'जस्टिस इज ड्यू' लिखा हुआ एक प्लेकार्ड भी रखा था. वहीं, जनवरी में दिल्ली में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक 40 वर्षीय बेकरी मालिक पुनीत खुराना ने तलाक की प्रक्रिया के दौरान आत्महत्या कर ली थी. परिवार ने पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

क्या आप भी बनना चाहते हैं
जनता की आवाज ?
तो जुड़िए रणजीत टाइम्स
न्यूज़पेपर के साथ और बनिए
जनता की सशक्त आवाज
आपकी खबर
आपकी ताकत!
जुड़ने के लिए अभी संपर्क करें
9827068888, 8224951278

ब्रेनडेड बुजुर्ग ने इंदौर, भोपाल मरीजों को दिया जीवनदान

जबलपुर, जबलपुर जिले में मानवता की मिसाल पेश करते हुए भेड़ाघाट निवासी 54 वर्षीय पूरनलाल चौधरी, जो बिल्डिंग मजदूर का काम करते थे, उनके अंगदान ने कई जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन दिया है. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती पूरनलाल का इलाज के दौरान ब्रेनडेड घोषित किया गया है. चिकित्सकों की प्रेरणा और परिवार की सहमति से बुजुर्ग के अंगदान की प्रक्रिया पूरी की गई. एक किडनी जबलपुर के निजी अस्पताल और दूसरी किडनी एयर एंबुलेंस से इंदौर के हॉस्पिटल भेजी गई. वहीं, लिवर को भोपाल भेजने की तैयारी की गई.

खास ग्रीन कॉरिडोर

इस खास ऑर्गन डोनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की मदद से शहर में दो ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए. इसमें NSCB मेडिकल कॉलेज से जबलपुर के एक निजी अस्पताल और NSCB मेडिकल कॉलेज से डुमना विमानतल तक इंदौर जाने के लिए बनाया गया है. इन ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से एक किडनी जबलपुर के निजी अस्पताल और दूसरी किडनी एयर एंबुलेंस से इंदौर के हॉस्पिटल भेजी गई. वहीं, लिवर को भोपाल भेजने की तैयारी की गई.

दिखाई मानवता की मिसाल

पूरनलाल चौधरी घर पर हुए हादसे में घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें मेडिकल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती किया गया. डॉक्टरों ने इलाज के दौरान ब्रेनडेड घोषित किया. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने परिवार को अंगदान के लिए प्रेरित किया, जिसपर परिवार ने सहमति जताते हुए बड़ा निर्णय लिया. ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम रातभर सक्रिय रही. अधिष्ठाता डॉ. नवनीत सक्सेना ने जानकारी दी कि जबलपुर, भोपाल और इंदौर के मरीजों से संपर्क किया गया, जिसके बाद अंगदान की प्रक्रिया पूरी की गई.

दूसरा सफल ऑर्गन डोनेशन

यह जबलपुर मेडिकल कॉलेज का इस साल का दूसरा सफल ऑर्गन डोनेशन है. बता दें कि इससे पहले 23 जनवरी को भी ब्रेनडेड मरीज के अंग भोपाल और इंदौर भेजे गए थे. पूरनलाल चौधरी के इस महादान ने कई मरीजों को नया जीवन देने का कार्य किया है. उनका यह कदम समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता और प्रेरणा का संदेश देता है

मध्यप्रदेश में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का बड़ा आंदोलन

8 साल से रुकी पदोन्नति को लेकर कर्मचारी हुए आक्रोशित, लाखों कर्मचारी रिटायरमेंट तक प्रमोशन से वंचित

भोपाल। मध्यप्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से लंबे समय से रुकी पदोन्नतियों को लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 8 वर्षों से पदोन्नतियां रुकी हुई हैं, जिससे न केवल कर्मचारियों की कार्यप्रेरणा में कमी आई है, बल्कि लाखों कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के समय तक बिना प्रमोशन के ही सेवा से निवृत्त हो गए। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिस तरह से विधि और विधायी कार्य विभाग में उच्चतम न्यायालय में प्रकरण दायर होने के बाद 48 तृतीय श्रेणी और 30 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई, उसी प्रकार अन्य विभागों में भी पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए। तिवारी ने कहा कि यदि विधि और विधायी विभाग में पदोन्नतियां दी जा सकती हैं तो अन्य विभागों में क्यों नहीं? कर्मचारी संघ का कहना है कि यह असमानता कर्मचारियों के बीच असंतोष का कारण बन रही है। संघ का यह भी आरोप है कि सरकार ने 2016 से पदोन्नति पर रोक लगाई हुई है, जिसके कारण लगभग 1 लाख से अधिक कर्मचारी बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस मुद्दे को लेकर संघ ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है।

● पदोन्नति के लाभः कर्मचारी संघ का तर्क

संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पदोन्नति ना केवल कर्मचारियों के आर्थिक लाभ को प्रभावित करती है, बल्कि इससे उनकी कार्य कुशलता और सम्मान में भी वृद्धि होती है। समय-समय पर पदोन्नति मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा, पदोन्नति से कर्मचारियों को नए पदनाम मिलते हैं, जो उन्हें सम्मान और अधिकारों का अहसास कराता है। यह पहली बार नहीं है जब कर्मचारियों ने पदोन्नति की मांग की हो। इससे पहले, पशुपालन विभाग में भी कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई थी, जबकि अन्य विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया रुकी हुई है। संघ का यह मानना है कि अगर किसी विभाग में पदोन्नति संभव है, तो दूसरे विभागों में भी इसे लागू किया जा सकता है, बशर्ते उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में निर्णय लिया जाए।

संघ की प्रदेश सरकार से मांग

संघ ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द 8 साल से रुकी हुई पदोन्नतियों पर फैसला लिया जाए और सभी कर्मचारियों को उनके अधिकार दिए जाएं। संघ का कहना है कि कर्मचारियों के सम्मान और कार्यकुशलता के लिए यह कदम जरूरी है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे कर्मचारी संघ के इस आंदोलन से प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। लाखों कर्मचारियों का यह मुद्दा गंभीर हो चुका है, और अगर इसे जल्द सुलझाया नहीं गया, तो यह सरकार के लिए चुनावी मुद्दा बन सकता है। कर्मचारियों की नाराजगी का असर सरकारी कार्यों में भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि पदोन्नति ना मिलने से कर्मचारियों का मनोबल कम हुआ है और उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा है।

प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला लाल टिपारा में भीषण आग, 10 हजार से ज्यादा गौवंश मौजूद

फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टला, गौवंश सुरक्षित

ग्वालियर। शहर के लाल टिपारा गौशाला में गुरुवार को एक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना उस समय हुई जब गौशाला के पास स्थित बाड़े में लगभग 1000 से अधिक गौवंश मौजूद थे। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इस बीच, नगर निगम के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव मदद प्रदान की। सूत्रों के मुताबिक, यह आग सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल पर बने टपरे में लगी थी, जहां गौशाला के कुछ कार्य और कार्यक्रम चलते रहते हैं। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और उसके आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल बना। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि जब आगजनी की घटना हुई, तब गौशाला प्रशासन और कर्मचारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी गौवंशों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

फायर ब्रिगेड की तत्परता से बड़ा हादसा टला

आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने अत्यधिक साहस और तत्परता से आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई की वजह से प्रदेश की पहली आदर्श गौशाला में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अगर आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जाता, तो स्थिति गंभीर हो सकती थी, क्योंकि गौशाला में इतनी बड़ी संख्या में गौवंश मौजूद थे। फिलहाल, आगजनी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारियों की टीम आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, आग सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल पर बने टपरे में लगी थी, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आग किस वजह से लगी। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है, और किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा नियमों की अवहेलना की जांच की जा रही है। लाल टिपारा गौशाला के प्रशासन ने दमकल विभाग और नगर निगम के अधिकारियों का धन्यवाद किया, जिनकी मदद से बड़ी संख्या में गौवंशों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गौशाला के एक अधिकारी ने कहा, ÷हमारी प्राथमिकता हमेशा गौवंशों की सुरक्षा और उनके कल्याण की रही है। समय रहते सभी को बाहर निकाल लिया गया और अब फायर ब्रिगेड की टीम आग को पूरी तरह से नियंत्रित कर रही है।÷

नगर निगम के अधिकारियों का भी अहम योगदान

नगर निगम के अधिकारियों ने भी आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम की मदद की और सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार का और नुकसान न हो। साथ ही, ग्वालियर नगर निगम ने गौशाला के आसपास सुरक्षा उपायों को और अधिक सख्त करने की योजना बनाई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

खंडवा जिले में जल जीवन मिशन में बड़ी धांधली, सब इंजीनियर निलंबित

खंडवा। जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में पीने का साफ पानी पहुंचाने की केंद्र सरकार की योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इस योजना को लेकर शिकायतों का सिलसिला लगातार बढ़ने के बाद, जिले के विधायक ने सांसद और कलेक्टर से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू हुई। जानकारी के अनुसार, खंडवा जिले के रांजनी, पांगरा और पोखर कला गांव में जल जीवन मिशन के तहत डाली गई पाइपलाइन में भारी अनियमितता पाई गई।यह पाइपलाइन ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए स्थापित की गई थी, लेकिन मौके पर जांच करने के बाद सामने आया कि पाइपलाइन की गुणवत्ता और कार्य की स्थिति उम्मीदों से कहीं अधिक खराब थी।इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, कलेक्टर ऋषव कुमार गुप्ता ने पीएचई (पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग) विभाग के सब इंजीनियर तरुण शर्मा को निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए,अपर कलेक्टर काशीराम बडोले ने कहा, ÷कलेक्ट्रेट सभागृह में हुई बैठक के दौरान इस योजना में अनियमितता की शिकायत की गई थी। इसके बाद सांसद, विधायक और अधिकारीगण ने मौके पर जाकर जांच की और पाइपलाइन में भारी गड़बड़ी पाई। इस कारण, पीएचई के उपयंत्री को निलंबित कर दिया गया है।÷

क्या था जल जीवन मिशन का उद्देश्य?

केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन, 2025 तक हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य था, लेकिन अब इसकी समयसीमा बढ़ाकर 2028 कर दी गई है। इस योजना के तहत देशभर में ग्रामीण इलाकों में हर घर को पाइपलाइन से पानी मुहैया करवाना था, ताकि लोग खुले में पानी की तलाश में न जाएं और साफ पानी का सेवन कर सकें। लेकिन, इस योजना में इस प्रकार की धांधली सामने आने से न केवल प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इस पूरे मिशन के कार्यान्वयन पर भी गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। खंडवा जिले में हुई यह घटना एक उदाहरण बन गई है कि कैसे बड़ी योजनाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार का ताना-बाना बुनकर सिस्टम को कमजोर किया जा रहा है। सब इंजीनियर तरुण शर्मा का निलंबन सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि सरकार ने भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई है। इस मामले में आगे और जांच हो सकती है, और दोषी पाए जाने पर और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यह घटनाक्रम जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम की सफलता पर सवाल उठाता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है और क्या इस योजना की बाकी प्रक्रियाओं में भी सुधार होगा।

प्रशासन का कड़ा संदेश

इस कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी योजनाओं के तहत काम करने वाले अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का पालन पूरी ईमानदारी से करना होगा, अन्यथा सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हों और जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को सही तरीके से पूरा किया जाए।

क्या है निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया?

देश में 2026 में जनगणना होनी है, जिसके चलते संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन भी किया जाएगा। इसको लेकर दक्षिण भारत के राज्यों का मानना है कि उनकी सीटें परिसीमन के बाद अन्य राज्यों के मुकाबले दक्षिण में सीटें ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगी। साल 2021 में देश की जनगणना होनी थी लेकिन कोरोनावायरस के चलते यह नहीं हो पाई थी। अब इस साल जनगणना होने की उम्मीद है। जनगणना के बाद ही निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी किया जाएगा।

संजय कुमार

पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान 2002 में संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन 2026 तक के लिए टाल दिया गया था। परिसीमन को लेकर कई दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता है कि उनकी सीटें उत्तर भारत के मुकाबले कम अनुपात में बढ़ सकती हैं। इसमें तमिलनाडु और केरल के जैसे राज्य शामिल थे। इसी के चलते गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते दक्षिण के राज्यों को विश्वास दिलाया था कि नए परिसीमन में उन्हें एक भी सीट का नुकसान नहीं होगा।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, प्राथमिक तौर पर निष्पक्ष तौर प्रतिनिधियो को निकायों में नागरिकों के प्रतिनिधित्व के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को लेटेस्ट जनसंख्या के अनुसार तय किया जाता है। इससे ही यह तय होता है कि एक सांसद या विधायक द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले लोगों की संख्या पूरे भारत में लगभग समान ही हो। परिसमीन, अनुच्छेद 81 के तहत 'एक नागरिक, एक वोट, एक मूल्य' का सिद्धांत निर्धारित करता है। संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर, राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजित किया जाएगा, जो कि संसद द्वारा निर्धारित अनुच्छेद 170(3) प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने÷ का पुनः समायोजन प्रदान करें। साधारण शब्दों में कहें तो कुल जनसंख्या के आधार पर संसद द्वारा तय मानकों के आधार पर होता है।

भारत में परिसीमन के इतिहास की बात करें तो

1951 की जनगणना के बाद, 1952 के परिसीमन आयोग अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के लिए पहला परिसीमन आयोग बनाया गया था। इन सीमाओं को बाद में 1962, 1972 और 2002 के परिसीमन आयोग अधिनियमों के तहत स्थापित परिसीमन आयोगों द्वारा तीन बार निर्धारित किया गया था।बता दें कि हाल ही में हुए परिसीमन में 2001 की जनगणना के आधार पर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया गया था। हालाकि, लोकसभा सीटों की संख्या प्रत्येक राज्य के लिए आवंटन और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या 1972 के परिसीमन के बाद से नहीं बदली है। 1971 की जनगणना के आधार पर, लोकसभा सीटों की संख्या 543 तय की गई थी, जिसका मतलब था कि प्रत्येक सांसद लगभग दस लाख भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम, 1976, जिसे आपातकाल की सरकार ने भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पारित किया था, उसके बाद 2000 के बाद पहली जनगणना होने तक लोकसभा सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया, और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस रोक कर कम से कम 2026 तक बढ़ा दिया था।

राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग की नियुक्ति होती है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके प्रतिनिधि तथा राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। इसके अलावा, परिसीमन से गुजरने वाले प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सहयोगी सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ये सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त मौजूदा सांसद और संबंधित विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त विधायक होते हैं।

इसके बाद, एसोसिएट सदस्य इनपुट और सलाह तो देते हैं लेकिन अगर किसी मुद्दे पर वोटिंग की बात होती है तो वे वोट देने के अधिकारी नहीं होते हैं। आयोग सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तथा इसके द्वारा निर्धारित संशोधित सीमाओं को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

परिसीमन में जनगणना के महत्व की बात करें तो जनगणना के आंकड़े परिसीमन का मुख्य आधार होते हैं। दक्षिणी राज्यों की आशंका का मुख्य मुद्दा यही जनसंख्या ही है। उन्हें डर है कि उत्तर भारतीय राज्यों की जनसंख्या नियंत्रण में विफलता के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, जबकि दक्षिण में जनसंख्या नियंत्रण तो सफल रहा, लेकिन संसद में प्रतिनिधित्व के मामले में जनसंख्या के चलते उन्हें नुकसान हो सकता है।जनगणना के आंकड़े भौगोलिक निकटता, जनसंख्या घनत्व और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए चुनावी सीमाओं को नए सिरे से निर्धारित करने में बेहद अहम होते हैं। खास तौर पर, डेटा से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महत्वपूर्ण आबादी वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि एससी/एसटी आबादी के हिस्से के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं। प्रस्तावित सीमाओं के निर्माण के बाद परिसीमन आयोग अपनी सिफारिशें जारी करता है और आम जनता, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करता है। आवश्यक संशोधन करने के बाद परिसीमन योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। आधिकारिक राज-पत्र में प्रकाशित होने के बाद, आयोग के आदेश अगले चुनाव में प्रभावी होते हैं।

आखिर कैसे रुकेगा निजी अस्पतालों में मरीजों का शोषण, जिम्मेदार कौन?

कमलेश पांडे

चिकित्सा पेशा या स्वास्थ्य व्यवसाय कोई सामान्य पेशा नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत जीवन और जनस्वास्थ्य से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें थोड़ी-सी भी लापरवाही किसी के जीवन पर भारी पड़ सकती है। वहीं, अपना या अपने परिवार का इलाज करवाने के चक्कर में यदि कोई व्यक्ति या परिवार लूट-पिट जाए तो यह भी प्रशासनिक नजरिए से अनुचित है। और ऐसे ही जरूरतमंद लोगों के पक्ष में सरकार और समाजसेवी संस्थाओं दोनों को अवश्य खड़ा होना चाहिए। यही वजह है कि जनस्वास्थ्य से जुड़े चिकित्सा पेशा या स्वास्थ्य व्यवसाय को सिर्फ कारोबारी लाभ के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ विषय (पेशा) है, जिसे जनसेवा की भावना से किया जाए तो सरकार और संस्था दोनों को यश मिलेगा। भारतीय सभ्यता व संस्कृति तो शुरू से ही सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे संतु निरामया की पक्षधर रही है। लेकिन देश में लागू नई आर्थिक नीतियों से उपजी नैतिक व कानूनी महामारी के दौर में जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। दुर्भाग्य है कि चिकित्सा पेशा भी इससे वंचित नहीं है। चर्चा है कि महज आर्थिक लाभ के उद्देश्य से चिकित्सक महंगी जांच और अनावश्यक दवाइयां लिख रहे हैं। जानलेवा ऑपरेशन करने और अंगों के कारोबार तक से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और न्यायिक जटिलताओं से ऐसे बहुत कम मामले हैं जो कोर्ट की दहलीज तक पहुंच पाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकारों से यह कहना कि वे प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के शोषण को रोकने के लिए उचित नीतिगत फैसला लें, देर आयद दुरुस्त आयद जैसा है। जनहित के इस सवाल पर राज्य सरकारों को तुरंत एक्शन में आना चाहिए। दरअसल, एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्राइवेट अस्पतालों और उनकी फार्मेसी में एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूली जा रही है। लिहाजा, कोर्ट ने इन अस्पतालों पर खुद से प्रतिबंध लगाने से इनकार किया और कहा कि ये संविधान में राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें ही इस पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार कर सकती है। वही उचित गाइडलाइंस बना सकती हैं। इसमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे न तो मरीजों और उनके परिजनों का शोषण हो और न ही प्राइवेट अस्पतालों के कामकाज पर बेवजह प्रतिबंध लगे। बता दें कि यह जनहित याचिका सिद्धार्थ डालमिया (कानून के छात्र) ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि %उनकी मां को पिछले साल कैंसर हुआ था और वह अब ठीक हो चुकी है। लेकिन उनके इलाज के दौरान प्राइवेट अस्पतालों में जबरन महंगी दवाएं खरीदनी पड़ीं। लिहाजा, इनकी गुहार है कि मरीजों और परिजनों को यह आजादी मिले कि वे अपनी पसंद की फार्मेसी से दवाएं, मेडिकल इक्विपमेंट आदि खरीद सकें। हालांकि, केंद्र ने कोर्ट में कहा है कि मरीजों पर विशेष फार्मेसी से दवाएं, मेडिकल इक्विपमेंट लेने की बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। भले ही बढ़ती आबादी के कारण सरकार को प्राइवेट अस्पतालों की मदद लेनी पड़ी, लेकिन इसमें मरीजों का शोषण नहीं होना चाहिए। हालांकि, निजी हॉस्पिटल्स में जिस तरह से कैशलेस इलाज का प्रचलन बढ़ा है, इस धंधे में बड़ी-बड़ी निजी कैशलेस चिकित्सा बीमा कम्पनियां सामने आयी हैं, उन्होंने अस्पतालों के पैनल जारी किए हैं, उससे एक संगठित लूट और इसी चक्कर में मानव स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ बढ़ा है। निजी अस्पतालों में तो चुपके चुपके नई नई दवाइयों का परीक्षण तक मानव शरीर पर हो जाता और किसी को भनक तक नहीं लगती। कुछ निजी अस्पताल व उनके डॉक्टर तो रक्त और मानव अंगों के अवैध कारोबार तक में शामिल हैं। ऐसे आरोप अक्सर मीडिया में उछलते रहते हैं। वहीं, जब से केंद्र सरकार गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड बनाने लगी है और 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने लगी है, तब से नए नए घोटालों और अनैतिक करतबों की बाढ़ आ चुकी है। इन सबके दृष्टिगत सरकार भले ही एहतियाती कार्रवाई करती आई है, फिर भी निजी चिकित्सा सेवा प्रदाताओं में इन नियमों का खौफ नहीं है। क्योंकि अक्सर चिकित्सक हड़ताल या दवा कारोबारी हड़ताल की धमकियां देकर हेल्थ सिंडिकेट से जुड़े लोग सरकार और प्रशासन को ब्लैकमेल कर लेते हैं। लेकिन सवाल फिर वही कि मानव स्वास्थ्य से खिलवाड़ कब तक। मसलन, जिस तरह से सिजेरियन बेबी का प्रचलन समाज में बढ़ रहा है, उससे कामकाजी महिलाएं भी भरी जवानी में बर्बाद हो रही हैं। ऐसे ही कई अन्य अस्वास्थ्यकर प्रचलन समाज में बढ़े हैं। किंतु हमारा स्वास्थ्य प्रशासन जनहित के दृष्टि से उतना संवेदनशील नहीं बना है, जितना उसे होना चाहिए। अन्यथा मिलावटी खाद्य पदार्थ, मिलावटी दवाइयों की बिक्री की बात सामने नहीं आती। याचिकाकर्ता ने भी दिलचस्प घपले की ओर इशारा किया है, लिहाजा कोर्ट का निर्देश समयोचित है। राज्य सरकारें जितनी जल्दी जग जाएं, केंद्र सरकार भी यथोचित जांच एजेंसी बनाए, अन्यथा इस गोरखधंधे पर काबू पाना मुश्किल है।

सिंगर हनीसिंह के शो के दौरान निम्नानुसार रहेगी यातायात व्यवस्था व डायवर्सन प्लान

इंदौर शहर में कल दिनांक 08.03.2025 को सिंगर हनीसिंह शो के मद्देनजर दोपहर 02:00 बजे से भारी वाहनों का प्रवेश पटेल नगर क्रॉसिंग हाईवे से दस्तूर चौराहा, स्टार चौराहा, रेडिसन चौराहा होते हुए देवास नाका तक होगा बंद ।

कार पास (स्टीकर) लगे वाहन ही वीआईपी द्वार तक जा सकेंगे । बायपास स्थित सी-21 इस्टेट ग्राउंड पर कल सिंगर हनीसिंह के होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर शो में आने वाली अपार भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने यातायात डायवर्सन व पार्किंग तक की यातायात व्यवस्था का प्लान तैयार किया है। प्लान के अनुसार, कल दोपहर 02:00 बजे से इस क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। वहीं, वीआईपी द्वार तक केवल वही वाहन जा सकेंगे, जिनपर कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा प्रदाय किये गये खास स्टीकर लगे होंगे। इउक्त कार्यक्रम में आने बाले श्रोताओं का रूट व पार्किंग की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :-

कनाडिया की ओर से आने वाले वाहनों का प्रवेश पटेल नगर कट से होते हुए हाईवे से बेस्ट प्राइज एवं वेलवेट गार्डन, लाभगंगा, आरई 2 रोड से होगा अथवा पटेल नगर कट से बांए मुडकर खजराना मार्ग से पाकिजा कॉलोनी के बाजू से दाहिने मुडकर आरई 2 रोड़ से होते हुए कार्यक्रम स्थल पार्किंग में पहुंचेंगे

रेडिसन चौराहे की ओर से आने वाले वाहन साईं कृपा कट, स्टार चौराहा, लाभगंगा होते हुए आरई 2 रोड से निर्धारित पार्किंग में आ सकेंगे। देवास की ओर से आने वाले वाहन चालक डीपीएस अंडरब्रिज से टीसीएल से दाहिने मुड़कर वेलवेट गार्डन तिराहा, लाभगंगा होते हुए आरई 2 मार्ग से प्रवेश कर पार्किंग में पहुंच सकेंगे और केवल वही वाहन वीआईपी द्वारं तक जा सकेंगे, जिनके वाहन पर कार पास (स्टीकर) लगे होंगे, ऐसे वाहन लाभगंगा होते हुए द पार्क होटल के सामने से होकर पतंग तिराहा, दस्तूर डिलाइट के सामने से होते हुए वीआईपी द्वार तक आ सकेंगे। कृपया परिवर्तित मार्ग का उपयोग कर यातायात व्यवस्था में सहयोग करें।

शिबानी को कहां से आया सीरीज 'डिब्बा कार्टेल' का आइडिया?

पिछले दिनों ओटीटी पर वेब सीरीज 'डिब्बा कार्टेल' का प्रीमियर हुआ। इस सीरीज को फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है और उनकी पत्नी शिबानी दांडेकर इससे क्रिएटर के तौर पर जुड़ी हैं। इस क्राइम ड्रामा का आइडिया शिबानी को कैसे आया, जानिए? शबाना आजमी के अलावा ज्योतिका, शालिनी पांडे, अंजलि आनंद और निमिषा सजयन जैसी उम्दा एक्ट्रेस ने वेब सीरीज 'डिब्बा कार्टेल' में ऐसी महिलाओं का रोल किया है, जो ड्रग, क्राइम के जाल में फंस जाती हैं। फिर ड्रग्स का बिजनेस करने लगती हैं। इस कहानी का आइडिया वेब सीरीज की क्रिएटर शिबानी दांडेकर को कैसे आया? इस सीक्रेट के बारे में शिबानी ने हाल ही में बताया है।

देखती रही हैं खूब क्राइम ड्रामा

शिबानी दांडेकर ने फर्स्टपोस्ट को दिए हालिया इंटरव्यू में बताया कि वह एक समय में बहुत ज्यादा क्राइम ड्रामा देखा करती थीं। ऐसे में अचानक उन्हें ख्याल आया कि क्राइम ड्रामा में महिलाओं की कहानी को दिखाया जाए। इस तरह वेब सीरीज 'डिब्बा कार्टेल' का आइडिया शिबानी दांडेकर को आया। शबाना आजमी इस सीरीज का हिस्सा इसलिए बनी हैं क्योंकि यह उनके लिए फैमिली प्रोजेक्ट की तरह है। वह रिश्ते में शिबानी की सास लगती हैं। शबाना आजमी ने जावेद अख्तर से शादी की है। फरहान अख्तर, जावेद अख्तर के बेटे हैं, वह उनकी पहली शादी से हुए हैं। शिबानी, फरहान की पत्नी हैं। ऐसे में शिबानी और शबाना रिश्ते में सास-बहू हैं। पिछले दिनों शबाना ने कहा था कि शिबानी ने इस वेब सीरीज को क्रिएट किया। वह कहती हैं, 'उसने मुझे हुक्म दिया, एक्टिंग करने के लिए। मैं बहू को कैसे मना कर सकती थी और बेटा (फरहान) तो प्रोड्यूसर ही है।

डिब्बा कार्टेल की स्टोरी काफी यूनीक नजर आती है। इसमें कुछ महिलाएं एक ड्रग माफिया चला रही हैं, लेकिन आम लोग उन्हें सिर्फ टिफिन सर्विस देने वाली महिलाएं समझते हैं।

रश्मिका मंदाना को आखिरी मिनट में तैयार होने की हड़बड़ी, उन्हें कॉलेज के दिनों की दिलाती है याद

रश्मिका मंदाना को अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई, जब आखिरी समय की हड़बड़ी के कारण उन्हें खुद ही अपने बाल और मेकअप करने पड़े। एनिमल अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, कभी-कभी, बस कभी-कभी चीजें आखिरी मिनट में होती हैं और मुझे खुद ही हेयर मेकअप स्टाइल करना पड़ता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त से मेरी तस्वीरें लेने के लिए कहना पड़ता है। इसका अंत इस तरह होता है। मुझे यह पसंद है। यह मुझे पूरी तरह से कॉलेज के दिनों में वापस ले जा रहा है। रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीर शेयर की। साड़ी में अभिनेत्री बेहद खूबसूरत लग रही थी। रश्मिका मंदाना सलमान खान की अगली फिल्म सिकंदर में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म निर्माताओं ने पहला गाना जोहरा जबीन रिलीज किया। सलमान खान और रश्मिका मंदाना को फराह खान की कोरियोग्राफी पर डांस नंबर पर परफॉर्म करते हुए देखा गया। ट्रैक की बीट्स प्रीतम ने तैयार की है। इस गाने को नक्श अजीज और देव नेगी ने अपनी मधुर आवाज में गाया है, जबकि इसके बोल समीर और दानिश सबरी ने लिखे हैं। सिकंदर 2023 की फिल्म टाइगर 3 के बाद सलमान खान की बड़े पर्दे पर वापसी है।

इस फिल्म का निर्देशन ए.आर. मुरुगादॉस ने किया है, जो गजनी के लिए प्रसिद्ध हैं। सिकंदर में सलमान खान और रश्मिका मंदाना के साथ, काजल अग्रवाल, सत्यराज, शरमन जोशी और प्रतीक बब्बर भी हैं।

एक अभिनेता के रूप में विनीत कुमार सिंह की रेंज बेहद शानदार

विनीत कुमार सिंह ने अपनी जगह बना ली है। और यह हम उनके हालिया रिलीज़ छावा और सुपरबॉयज़ ऑफ़ मालेगांव में लगातार दिल जीत लेने वाली परफॉर्मेंस के बाद पूरे यकीन से कह सकते हैं। लक्ष्मण उटेकर और रीमा कागती के निर्देशन में बनी फिल्मों में अपने किरदार कवि कलश और फरोग के लिए अभिनेता को खूब प्रशंसा मिल रही है। और जबकि अभिनेता अपनी हालिया रिलीज़ सुपरबॉयज़ ऑफ़ मालेगांव की सफलता का जश्न मना रहे हैं, यहाँ विनीत की कुछ अन्य फ़िल्में हैं, जो आपको साबित करेंगी कि उन्होंने एक अभिनेता के रूप में कभी भी प्रयोग करना बंद नहीं किया। मुक्काबाज़ एक ऐसी फ़िल्म है जो कई कारणों से विनीत के दिल के हमेशा करीब रहेगी।

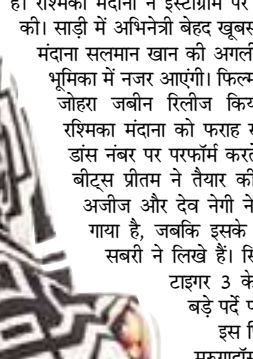

मौनी रॉय ने अपनी अद्भुत कथक प्रस्तुति से सभी को किया मोहित

मौनी रॉय एक ऑल-राउंडर हैं। वह एक बहुत ही लोकप्रिय अभिनेत्री, एक सफल एंटरप्रेन्योर और एक फैशनिस्टा आइकन होने के साथ-साथ डांस में भी गहरी रुचि रखती हैं। मनोरंजन जगत में अपने करियर की शुरुआत बैकग्राउंड डांसर के रूप में करने वाली मौनी के लिए नृत्य हमेशा से उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। कला के प्रति उसी प्रेम को प्रदर्शित करते हुए, मौनी रॉय ने अपने सोशल मीडिया पर लोकप्रिय बंगाली गीत शोंगो चारे कोरे सखी की धुन पर शानदार कथक डांस प्रस्तुत किया।

मौनी की कथक नृत्य में महारत, उनकी आंखों की भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता और उनकी बेहतरीन मुद्राएँ (हस्त मुद्राएँ) - इन सभी ने हमें एक बार फिर उनका दीवाना बना दिया।

कुल मिलाकर, उनकी इस प्रस्तुति में उनके डांस के प्रति असीम प्रेम की झलक पूरी तरह से नजर आई।

काम के मोर्चे पर, मौनी हाल ही में लंदन फैशन वीक 2025 की सफल यात्रा से लौटी हैं, जहाँ वह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र भारतीय चेहरा थीं। अभिनेत्री जल्द ही अपनी अगली रिलीज़ द भूतनी के साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी, जो 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

'बॉलीवुड 800 करोड़ रुपये वाली फिल्म के पीछे भाग रहा है', निर्देशक ने छोड़ा मुंबई

अनुराग कश्यप लंबे समय से मुंबई छोड़ने की बात कर रहे हैं। खबर है कि वह अब मुंबई से दक्षिण भारत में जाकर शिफ्ट हो चुके हैं। हाल ही में निर्देशक ने एक इंटरव्यू में फिर से बताया कि वह क्यों बॉलीवुड से परेशान हैं। अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड में लीक से हटकर फिल्में बनाई हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से वह बॉलीवुड के वर्क कल्चर को लेकर काफी परेशान नजर आए। इसलिए निर्देशक ने मुंबई छोड़ने का मन बनाया। वह अब मुंबई से दूर दक्षिण भारत में जाकर बस गए। हाल ही में अनुराग कश्यप ने फिर से बॉलीवुड के खराब वर्क कल्चर को लेकर बात की।

भोपाल सेंट्रल जेल के विचाराधीन कैदी की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने लगाए पुलिस-जेल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप

रवि सिंह,

भोपाल। भोपाल सेंट्रल के विचाराधीन कैदी की शुक्रवार तड़के मौत हो गई। पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि उन्हें पुलिस और जेल प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। केस की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। भाई सुरेंद्र जैन ने बताया कि प्रकाश चंद्र जैन (42) बाड़ी जिला रायसेन में रहते थे और पेशे से पत्रकार थे। उन्हें हमीदिया अस्पताल में पेट की तकलीफ के बाद भर्ती कराया गया था। शुक्रवार तड़के संदिग्ध हालात में मौत हो गई। भाई सुरेंद्र का आरोप है कि बाड़ी पुलिस ने अड़ीबाजी के झूठे केस में उन्हें जेल भेजा। जिस रितिक जैन की शिकायत पर प्रकाश को अड़ीबाजी का आरोपी बनाया गया वह स्वयं थाने का लिस्टेड बदमाश है। क्योंकि भाई पत्रकारिता के माध्यम से समय-समय पर स्थानीय पुलिस के भ्रष्टाचार को उजागर करता था, इस कारण उसे फंसाया गया और जेल भेजा। स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्हें रायसेन जेल से भोपाल सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया। 14 फरवरी से भोपाल जेल में बंद थे। उनके लिवर में तकलीफ थी, जेल के अस्पताल में चेकअप के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें अपशब्द कहे। यहां तक की उनकी बीमारी को झूठा बोला और मारा-पीटा भी गया। यह तमाम बातें भाई ने उन्हें जेल में मिलने के दौरान बताई थी। मृतक की पत्नी चांदनी जैन का आरोप है कि जेल प्रशासन द्वारा पति को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। जेल में हर बार मुलाकात होने पर वह यह शिकायत करते थे। जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार करने को लेकर हमने सीएम हैल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी।

भोपाल में इंजीनियरिंग कर रही छात्रा ने किया सुसाइड, परिजनों ने एक युवक पर लगाए गंभीर आरोप

रवि सिंह

भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में इंजीनियरिंग कर रही एक छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया और सुसाइड कर लिया है। यह घटना गुरुवार की है, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक युवक की प्रताड़ना से युवती परेशान थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। युवती का नाम साक्षी था जो कुटीर नगर में रहती थी। वह निजी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। गुरुवार को साक्षी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, उसकी तबीयत बिगड़ी तो छात्रा को तत्काल अस्पताल ले जाया गया यहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।

शरीर में आयरन बढ़ाने के लिए इन 6 चीजों का सेवन करें

विटामिन, कैल्शियम आदि पोषक तत्व की तरह आयरन शरीर के लिए जरूरी है। इसकी कमी से शरीर में भारी कमजोरी आती है और खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। आयरन बढ़ाने के लिए 6 चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए।

जिस जमीन में नमी, पोषण और ताकत नहीं होती, उसे बंजर कहते हैं। इसी तरह आयरन की कमी शरीर को बंजर बना देती है। यह बॉडी का खून, रेड ब्लड सेल्स और ऑक्सीजन कम कर देती है। आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए कुछ उपाय अपनाते रहने चाहिए। जिनके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने जानकारी दी है।

आयरन की कमी से होने वाले रोग

आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं। जिस वजह से एनीमिया यानी खून की कमी का खतरा बढ़ जाता है। यह दिक्कत महिलाओं को सबसे ज्यादा होती है। इसलिए सरकारी स्कूलों में बचपन से ही लड़कियों को आयरन की गोली खिलाई जाती है।

होने के लक्षण जानते हैं।

ये लक्षण कर देंगे बुरा हाल

ऑस्ट्रेलिया की सरकारी हेल्थ बेवसाइट के अनुसार आयरन की कमी शरीर के लिए खतरनाक हो सकती है। जिसकी वजह से निम्नलिखित लक्षण व संकेत दिख सकते हैं।

- हमेशा थकावट रहना
- सांस फूलना
- सिर घूमना
- खून की कमी
- रंग पीला पड़ना
- हाथ-पैर ठंडे होना
- जीभ में सूजन आना
- बार-बार इंफेक्शन होना
- इम्यून सिस्टम की कमजोरी
- बच्चों का विकास रुकना
- भूख ना लगना
- कमजोर नाखून, आदि

आयरन बढ़ाने के उपाय

इन 6 फूड्स को आयरन का भंडार बताया है। इन वेज फूड को डाइट में शामिल करने के बाद आयरन कम होने का खतरा काफी कम हो जाता है।

इसके लिए आप राजगिरा (चौलाई), रागी, किशमिश, दाल, सोयाबीन, करी पत्ता का सेवन बढ़ाएं।

किसमें कितना आयरन?

- 25 ग्राम राजगिरा में 2.8 मिलीग्राम आयरन
- 20 ग्राम रागी में 1.2 मिलीग्राम आयरन
- 10 ग्राम किशमिश में 0.7 मिलीग्राम आयरन
- 30 ग्राम दाल में 6.6 मिलीग्राम आयरन
- 30 ग्राम सोयाबीन में 2.4 मिलीग्राम आयरन
- 10 ग्राम करी पत्ता में 0.87 मिलीग्राम आयरन

इस वजह से भी कम हो सकता है आयरन

खून बहना, पर्याप्त पोषण ना मिलना आदि कारणों से आयरन डेफिशिएंसी होती है। लेकिन कई बार इसके पीछे आयरन का खराब अवशोषण भी होता है। मतलब आप आयरन देने वाली चीजें खा तो रहे हैं, लेकिन शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है।

आयरन का इस्तेमाल बढ़ाने के तरीके

- आयरन फूड के साथ विटामिन-सी देने वाले फूड भी खाएं
- खाने के बाद कॉफी और चाय पीने से बचें
- अनाज को खाने से पहले पानी में भिगोएं, अंकुरित और फर्मेंट करें
- लोहे की कढ़ाई या पैन में खाना बनाएं
- लाइसीन अमिनो एसिड और आयरन देने वाला क्विनोआ और फलियां खाएं

यूरिक एसिड को जोड़ों में गला देंगे ये आयुर्वेदिक तरीके

शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से आपको गाउट या किडनी की पथरी की समस्या हो सकती है, इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने और इसके लक्षणों को कम करने के लिए आप कुछ आयुर्वेदिक तरीके आजमा सकते हैं, जो असरदार हैं।

यूरिक एसिड बढ़ना एक आम समस्या बनती जा रही है. शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने से हाइपरयुरिसीमिया या गाउट की बीमारी हो सकती है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जोड़ों में गंभीर सूजन और दर्द पैदा कर सकता है। यह किडनी की पथरी का भी कारण बन सकता है। प्यूरीन नामक रसायन के टूटने से यूरिक एसिड निकलता है। प्यूरीन मानव शरीर में पहले से मौजूद होता है। इसके अलावा खाने-पीने की चीजों में भी यह रसायन होता है। वैसे तो यूरिक एसिड किडनी द्वारा फिल्टर होकर पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है लेकिन जब इसका लेवल ज्यादा हो जाता है, तो यह जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है और परेशानी पैदा करता है।

यूरिक एसिड कैसे कम करें?

यूरिक एसिड कम करने के लिए कई दवाएं और मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं लेकिन आप कुछ गाउट या यूरिक एसिड के लिए आयुर्वेदिक उपचार भी आजमा सकते हैं।

यूरिक एसिड का आयुर्वेदिक उपचार त्रिफला

आयुर्वेद की तीन शक्तिशाली जड़ी बूटियों भीभीतकी, हरीतकी और आंवला से मिलकर बना त्रिफला यूरिक एसिड का बढ़िया उपचार है। इसके एंटीऑक्सिडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण इसे मजबूत औषधि बनाते हैं। इसके लिए आप सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी के साथ एक चम्मच त्रिफला पाउडर ले सकते हैं।

गाउट का आयुर्वेदिक उपचार- हल्दी

लगभग सभी आयुर्वेद दवाओं में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें करक्यूमिन होता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। हल्दी गठिया का असरदार इलाज है। सूजन और दर्द को कम करने के लिए प्रभावित हिस्से में हल्दी का पेस्ट लगाया जा सकता है, फायदा मिलेगा।

यूरिक एसिड की रामबाण दवा है अदरक

गाउट या गठिया के रोगियों के लिए निर्धारित हर्बल दवाओं में अदरक मिलाया जाता है। इसमें हाई यूरिक एसिड को कम करने के ताकत होती है। यूरिक एसिड कम करने और इसके लक्षणों को कम करने के लिए आपको अपने खाने और चाय में अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए।

यूरिक एसिड का घरेलू इलाज है गिलोय जड़ी बूटी

गिलोय को मूल रूप से एक ज्वरनाशक जड़ी बूटी कहा जाता है। इसे शरीर में एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को बेअसर करने के लिए जाना जाता है। यूरिक एसिड लेवल कम करने के लिए आप एक्सपर्ट की सलाह पर गिलोय जूस ले सकते हैं या इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं।

यूरिक एसिड की आयुर्वेदिक दवा है नीम

नीम को सदियों से औषधीय पौधा माना जाता रहा है। नीम में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो इसे गाउट के उपचार के लिए एक बढ़िया जड़ी बूटी बनाते हैं। अगर आप यूरिक एसिड के मरीज हैं, तो दर्द और सूजन कम करने के लिए प्रभावित हिस्से पर नीम का पेस्ट लगाएं।